millers/traders and to improve rice procurement. Basmati rice meant for export is however exempted from levy. Millers/dealers have also been given the option to tender levy on Basmati in the form of any other acceptable variety.

The procurement prices are as follows:

State/U.T.	Rs. Per Quintal
Haryana	331.15
Punjab/Chandigarh Administration	329.45
Rajasthan	316.65
Uttar Pradesh	303.10
West Bengal	299.60
Delhi Administration	310.00

Some representations against the reintroduction of basmati levy have been received.

दिल्ली में स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये विकास के कार्य में प्रगति

1028. **श्री राम जेठमलानी :**

सरदार जगजीत सिंह अरोरा :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विकास कार्य सरकार की योजना के अनुसार चल रहा है ;

(ख) यदि हां तो 1987-88 के वर्ष में सरकार ने कितने स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया था और इस हेतु कितनी धन-राशि आबंटित की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि यह आबंटित धनराशि इसी मद पर खर्च की गई और स्लम क्षेत्रों का विकास लक्ष्य के अनुसार हुआ ; और

(घ) यदि नहीं, तो वस्तु-स्थिति क्या है और विकास कार्य के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निष्पादित न किए जाने के क्या कारण हैं ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1987-88 के लिए विभिन्न स्लम क्षेत्रों में रह रहे 2 लाख स्लम निवासियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके लिए 6 करोड़ रुपए का नियतन किया गया था ।

(ग) जी हां ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली के गांवों का लाल डोरा क्षेत्र बढ़ा कर उनका विकास किया जाना

1029. **श्री राम जठ मलानी :**

श्री राम नरेश यादव :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान सातवीं पंचवर्षीय योजना के काल में दिल्ली के गांवों का लाल डोरा क्षेत्र बढ़ा कर उनके विकास का निर्णय किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने गांवों को लिया गया था; और सातवीं पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बीत जाने पर अभी तक कितने गांवों का लाल डोरा क्षेत्र बढ़ाया गया है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "ना" हो, तो उसके क्या कारण हैं

और इस कार्य को गति देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). 82 गावों जिनके वर्ष 2001 तक शहरीकृत होने की संभावना नहीं थी, की भूमि जोतों की चकबन्दी की एक योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया । 8 गांवों में कार्यवाही की गई थी । बढ़ाया गया लाल डोरे को सुविधा 5 गांवों में दी गई है । चकबन्दी कार्यवाहियां रोकने के लिए अभ्यावेदन दर अभ्यावेदन प्राप्त होने के कारण अन्य 3 गांव में कार्य नहीं किया जा सका । इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत 15 और गावों अधिसूचित किये गये है । इस योजना के अन्तर्गत गांवों के विकास में कृषि भूमि के स्थान पर रिहायशी भूमि देने का प्रावधान शामिल है और गांव के भूमिहीन कृषि मजदूरों को रिहायशी भूखंड भी दिए जाते है तथा इस प्रकार विस्तारित आबादी को "विस्तारित लाल डोरा" के रूप में जाना जाता है ।

Autonomy to Akashvani and Doordarshan

1030. SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is any fresh thinking on giving autonomy to Akashvani and Doordarshan;

(b) whether an Autonomous Corporation is proposed; and

(c) if so, by when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) Both All India Radio and Doordarshan enjoy complete functional autonomy in all professional aspects.

(b) No, Sir;

(c) Government is of the view that the media are meant to serve the people and for such a purpose, it is not necessary that they should be set up as statutory bodies/corporations.

Supplies of Confiscated goods to various primary stores of Delhi by NCCF

1031. SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of a *prima facia* case of connivance of NCCF's Branch Manager, Delhi and Branch Officers in issusing large scale authorisations on other branches of NCCF for supply of confiscated goods to various primary stores of Delhi during 1987 and 1988;

(b) what was the basis/criterion of such allotments;

(c) whether it is a fact that financial capacity of the stores and retailing facilities of large quantities of confiscated goods by them was not assessed by the Branch Manager before issuing such authorisations;

(d) whether it is also a fact that the GTRs were delivered to the Stores in Delhi in violation of the Sales Tax Regulations for such Inter-State Sales; and

(e) if so, the details thereof and what action has been taken/proposed to be taken against the Branch Manager and branch officers?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) to (e) A complaint in this regard has been received by the NCCF which is under investigation.

Import of Black Matpe by NCCF

1032. SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether NCCF imported huge stocks of Black Matpe from Thailand in